

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 13/21

सन् 2021

जीसीएमएस संख्या 2021/153

बउनवानी-1. रामधन पुत्र श्योपाल मीना निवासी ग्राम नीदंडदा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
बनाम

1. मोहन पुत्र हरनाथ योगी नि० बीड का टापरा भगवतगढ तह. चौथ का बरवाडा
2. सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 616/2021 निर्णय दिनांक 5.4.2021 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री हिम्मत सिंह

वकील अपीलान्ट

2. श्री श्यामसुन्द गुप्ता

वकील रेस्पो. संख्या 1

2. श्री तौफिक मोहम्मद

पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :-

दिनांक 06.01.2022

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 616/2021 में पारित निर्णय दिनांक 5.4.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम भगवतगढ की भूमि आराजी ख०न० 2000 रकबा 0.32 है० पर से अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पो. संख्या 1 को बेदखल करने बाबत पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एवं विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2077 में ग्राम भगवतगढ बी की भूमि ख०न० 2000 रकबा 0.32 है० किस्म बारानी-2 पर अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 तारामीरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिये जाने के आशय की रिपोर्ट पटवारी द्वारा प्रस्तुत की जाने पर उभय पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का अवसर दिये जाने पर अपीलान्ट एवं रेस्पो.संख्या 1 का विवादित भूमि पर अपना-अपना स्वयं कब्जा होना बताया जाने पर दिनांक 5.4.2021 को पुनः मौका देखा गया एवं पडौसियों से पुछताछ की जाने खसरा परिवर्तनशील सम्बत् 2071 से 2076 के अनुसार उक्त भूमि पर रेस्पो.संख्या 1 पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण रेस्पो. संख्या 1 को ख०न० 2000 रकबा 0.32 है० पर से बेदखल करने के साथ-साथ लगान 2.56 का 50 गुना 128/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। स्वतंत्र गवाहों के लिये गये बयान के आधार पर रेस्पो. का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है क्योंकि अदालत मातहत ने सम्बत् 2071-2074 की खसरा गिरदवारी के आधार बनाकर मिथ्या आदेश पारित किया गया जबकि इससे पूर्व के समस्त रिकार्ड में अपीलान्ट व उसके पिता श्योपाल का नाम खसरा गिरदवारी में दर्ज है। वर्तमान ख०न० 2000 का पुराना खसरा नम्बर 1686 है० खसरा नम्बर 1686 पर सम्बत् 2028 से पूर्व से ही अपीलान्ट के पिता श्योराम पुत्र भोरया मीना का कब्जा था अपीलान्ट के पिताजी श्योपाल जब तक जिन्दा रहे तब तक उक्त भूमि पर वे खेती करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती करता रहा है। किन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो. संख्या 1 का एक का विवादित भूमि के आसपास कोई खेत नहीं है जबकि विवादित भूमि की सीमाएं व अपीलान्ट के

64
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

...(1).....

(अपील संख्या 13/2021 उनवानी रामधन बनाम मोहन लाल वगै व अन्य)

खेत की सीमाएँ आपस में मिल रही हैं। रेस्पो. संख्या 1 अपीलान्त के खेत पर मजदूरी का कार्य करता था जिससे राजस्व अधिकारियों से साज कर गलत एवं मिथ्या तरीके से स्वयं के नाम खसरा गिरदावरी करवाली है अदालत मातहत द्वारा आज भी अपीलान्त का विवादित भूमि पर कब्जा माना है इसलिए अदालत मातहत ने कृषि वर्ष, 2077 में खसरा नम्बर 2000 में 0.32 ऐयर पर अपीलान्त का अतिक्रमण मानते हुए पुनः नोटिस जारी किया है। यह है कि आदेश जैर अपील की जानकारी दिनांक 1.7.2021 को होने पर जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है। इसलिए अपील अपीलान्त स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्त ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूमि सरकारी भूमि है जिसपर रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण उसके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्त के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किये हैं इसलिए उसको अपील करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकारा राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि ख0न0 2000 रकबा 0.32 है0 पर मेरा सम्बन्ध 2065 से लगातार कब्जा काश्त होने के कारण अदालत मातहत द्वारा मेरे नाम नोटिस जारी किये जाकर मुझे बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं। यह तर्क भी दिया कि विवादित भूमि पर कब्जा होने बाबत स्वतंत्र गवाहों के बयान भी लिये गये हैं जिसमें सभी गवाहों द्वारा उक्त विवादित भूमि पर मेरा कब्जा काश्त बताया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त एवं रेस्पो. को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों से हो जाती है। यद्यपि पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्त एवं रेस्पो. संख्या 1 का विवादित भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है किन्तु किसका कितने भाग पर अतिक्रमण है स्पष्ट नहीं होने पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 5.4.2021 को विवादित भूमि का मौका देखा गया है तथा दौराने मौका निरीक्षण विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत गवाहों के बयान लिये जाने पर रेस्पो. संख्या 1 का अतिक्रमण साबित होने पर रेस्पो. संख्या 1 को उक्त भूमि पर से बेदखल करने एवं लगान 2.56 का 50 गुना 128 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर